साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

भोपाल, सोमवार, 15-21 अप्रैल 2024 वर्ष-9, अंक-52

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

चौपाल से भोपाल तक

हमारे किसान कैसे बनेंगे आत्मनिर्भरः कहीं टेक्नीशियन, तो कहीं मशीनें ही नहीं

-प्रदेश के 20 जिलों में 122 लैब में से 102 बंद मिलीं
-हर साल 1.29 करोड़ सिर्फ बिजली का बिल आ रहा
-बड़वानी के सात ब्लॉक में लैब पर छह बंद पड़ी

मिट्टी की जांच करने वाली 80% लैब बंद

भोपाल। जागत गांव हमार

सरकारी पैसा मिट्टी में कैसे मिलाया जाता है, इसका उदाहरण देखना है तो मध्यप्रदेश के किसी भी ब्लॉक की मिट्टी परीक्षण लैब देख लें। प्रदेश के 52 जिलों में 153 करोड़ खर्च कर बनीं इन 265 लैब में से 215 में कहीं ताले पड़े हैं तो कहीं ये चालू नहीं हुईं। लैब खोलने के पीछे मकसद था किसानों को जमीन की उर्वरा क्षमता बताना, जिससे वे सही खाद का इस्तेमाल कर अच्छी फसल ले सकें। लेकिन, शायद ही किसी किसान को इस लैब से फायदा पहुंचा हो।

वजह- इन लैब में मशीनें और उपकरण तो लगा दिए गए, लेकिन जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन और कृषि अधिकारियों की भर्ती ही नहीं हुई। '**जागत गांव हमार**' ने प्रदेशभर की ऐसी 122 लैब में पड़ताल की तो 102 ऐसी मिलीं, जिनमें कहीं अनाज रखा था तो कहीं कृषि कार्यालय चल रहे हैं। इन लैब पर हर साल 1.29 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली बिल के नाम पर खर्च हो रहे हैं। केवल जिला मुख्यालय की लैब ही चालू है। दूर- दराज से किसानों को जिले की लैब जाना पड़ रहा है।

खंडवा में महंगी टाइल ले गए चोर- पुनासा, पंधाना और छैगांव माखन तहसीलों में लैब बंद पड़ी हैं। किसानों ने बताया कि लैब में कर्मचारी और मशीन दोनों नहीं हैं। मिट्टी की जांच के लिए निजी लैब जाना पड़ता है। कई जगह झाड़ियां उग आई हैं। यहा चोर महंगी टाइल ही उखाड़ ले गए हैं।

सीहोर लैब में अनाज की बोरियां

सीहोर जिले के आष्टा स्थित लैब पर ताला लगा है। बाहर अनाज की बोरियां रखी हैं। किसानों ने बताया कि ये सिर्फ नाम की लैब है। नमूने सीहोर ही जाते हैं। यहां तो अनाज गोदाम बन गया है। इछावर में लैब खुली है, पर यहां जांच नहीं होती। दो महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

बड़वानी लैब में लगा ताला

बड़वानी जिले के सात ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण लैब हैं, लेकिन छह बंद पड़ी हैं। एक में व्यवस्था है, लेकिन जांच की पूरी सुविधाएं नहीं हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि राजपुर में दो साल पहले लैब बनी, लेकिन कभी खुली नहीं। बड़वानी में लैब है, जहां पर स्टाफ व मशीनें पर्याप्त नहीं होने से जांच नहीं रही है।

52	जिला
265	जांच लैब
215	में ताला
122	लैब की पड़ताल
102	की हालत खराब
153	करोड़ रु. खर्च

बंद होने की दो वजह

एकः लैब में स्टाफ नहीं| एक लैब में कम से कम 5 स्टाफ की नियुक्ति करनी थी। जांच अधिकारी। दो तकनीकी सहायक और दो कर्मचारी। यानी 265 लैब में 1,325 भर्ती। यह नियुक्ति नहीं हुई।

दोः कहीं उपकरण नहीं| 25 प्रतिशत लैब में जरूरी मशीनें नहीं लगाई गईं। इन्हें परीक्षण केंद्र बना दिया गया। प्रदेश में ऐसी 66 लैब हैं। इससे किसानों में आक्रोश पनप रहा है। जांच नहीं हो पा रही है।

मिट्टी की उर्वरक क्षमता सही रखने के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है। इससे पता चलता है कि कौन सा तत्व कम हो रहा है और कैसे उर्वरक क्षमता बढ़ाई जा सके। मिट्टी लैब तत्काल चालू होनी चाहिए। नहीं तो इसका असर उत्पादन पर नजर आएगा। लगातार मिट्टी की जांच न होने से खेत प्रभावित हो रहे हैं।

जीएस कौशल, सेवानिवृत्त कृषि संचालक, मप्र

मप्र में सवा करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 265 लैब बनाईं और 153 करोड़ खर्च किए, फिर भी लैब बंद हैं, इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं। मिट्टी परीक्षण लैब को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और इन्हें चालू करने के लिए नीति बनाई जाएगी। किसानों की परेशानी जल्द दूर होगी।

अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग

मध्यप्रदेश में अब दागदार गेहूं भी खरीदेंगी समितियां

भोपाल। जागत गांव हमार

पिछले दिनों से गेहूं की खरीदी शुरू होने के बाद किसानों का दागी गेहूं खरीदने से समितियां इंकार कर रही थी। कुछ सोसाइटियों ने दागी गेहूं खरीद लिया था। उसको भारतीय खाद्य निगम ने वापस कर दिया था। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आपत्ति उठाई थी और सरकार से कहा था कि रंग विहीन और मामूली दागी गेहूं को भी खरीदा जाए।

- केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए निर्देश
- 30 प्रतिशत तक दागी गेहूं के भाव में भी कोई कटौती नहीं होगी
- संयुक्त किसान मोर्चा की चेतावनी के बाद सरकार हुई सक्रिय

मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर तत्काल तो कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन इसे लेकर केंद्र सरकार से मांग की थी जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र द्वारा निर्देशित किया है कि अब बगैर किसी भावों की कटौती के किसानों का बारिश के कारण खराब हुआ गेहूं भी खरीदा जाए। हालांकि उस पर 30 प्रतिशत तक का बंधन जरूर लगाया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि दागी गेहूं में किसानों का नुकसान न हो, ऐसी व्यवस्था करें, और जितना भी गेहूं खरीदा जाए उसको अलग रखकर जल्द से जल्द उसका वितरण में निपटारा किया जाए।

बगैर कटौती मिलेगा भाव

किसान नेताओं ने बताया कि इस मुद्दे को कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के सामने भी भोपाल में उठाया था। दो दिनों से किसानों ने सोसाइटियों पर गेहूं ले जाना बंद कर दिया था। अब केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के उपयुक्त विश्वजीत हलदर ने मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि किसान यदि 30 प्रतिशत तक दागी गेहूं लेकर आता है तो उसको बगैर किसी भाव की कटौती के खरीदा जाए।

घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को सालाना लगभग 350 लाख टन यूरिया की जरूरत

2025 के अंत तक यूरिया का आयात होगा बंद

अब यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा, क्योंकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन से आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटने में मदद मिली है। भारतीय कृषि के लिए उर्वरकों की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। देश पिछले 60-65 वर्षों से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहा है। लेकिन अब सरकार नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम इसे बढ़ावा दे रहे हैं। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बारे में पूछे जाने पर मंडाविया ने कहा कि मोदी सरकार ने यूरिया आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए दोतरफा रणनीति अपनाई है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने चार बंद यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया है और एक अन्य कारखाने को पुनर्जीवित कर रही है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को सालाना लगभग 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है।

यूरिया उत्पादन में बंपर बढ़ोतरी

मंडाविया ने कहा कि स्थापित घरेलू उत्पादन क्षमता 2014-15 में 225 लाख टन से बढ़कर लगभग 310 लाख टन हो गई है। वर्तमान में, वार्षिक घरेलू उत्पादन और मांग के बीच का अंतर लगभग 40 लाख टन है। पांचवें संयंत्र के चालू होने के बाद यूरिया की वार्षिक घरेलू उत्पादन क्षमता लगभग 325 लाख टन तक पहुंच जाएगी और लक्ष्य 20-25 लाख टन पारंपरिक यूरिया के उपयोग को नैनो तरल यूरिया से बदलने का है। हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 2025 के अंत तक पीएम मोदी यूरिया पर देश की आयात निर्भरता खत्म कर देंगे। यूरिया का आयात बिल शून्य हो जाएगा।

आयात में भारी गिरावट| सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2022-23 में यूरिया का आयात पिछले साल के 91.36 लाख टन से घटकर 75.8 लाख टन रह गया। 2020-21 में यूरिया आयात 98.28 लाख टन, 2019-20 में 91.23 लाख टन और 2018-19 में 74.81 लाख टन रहा। मंडाविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है। केंद्र ने प्रमुख फसल पोषक तत्वों पर सब्सिडी बढ़ाकर भारतीय किसानों को वैश्विक बाजारों में उर्वरकों की कीमतों में तेज वृद्धि से भी बचाया है। सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के मुकाबले 1.64 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी आवंटित की है।

सात करोड़ नैनो यूरिया बोतलें बिकीं| अगस्त 2021 और फरवरी 2024 की अवधि के दौरान कुल 7 करोड़ नैनो यूरिया बोतलें (प्रत्येक 500 मिलीलीटर की) बेची गई हैं। नैनो यूरिया की एक बोतल पारंपरिक यूरिया के एक बैग (45 किलोग्राम) के बराबर है। सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को प्रोत्साहित करने के लिए धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) योजना भी शुरू की है।

खुराक का बजट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए सरकार ने किया

मुरैना की 25 गौशालाओं में भूसा घोटाला, अनुदान के नाम पर खेल

अवधेश डंडोतिया, मुरैना। जागत गांव हमार

प्रदेश की गौशाला में जिन गायों को रखा जा रहा है, उनकी खुराक का बजट 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। लेकिन इस बजट का भी कई जगह दुरुपयोग हो रहा है। मुरैना जिले में गौशाला के नाम पर मिलने वाले अनुदान में बड़ा खेल चल रहा है। जिन गौशालाओं में गाय ही नहीं है, वहां भी अनुदान दिया जा रहा है। कई गौशालाओं में जितने पशु हैं, उससे कई गुना पशु बताकर भूसा मंगाया जा रहा है। छह गौशालाओं में गाय व नंदी को कैदियों की तरह ठूंस दिया गया है। सिंगारदे की गौशाला में गांव के गाय तो नहीं हैं, लेकिन दूसरे गांव के एक व्यक्ति के सांड और गायों को रखा गया है, लेकिन इन मवेशियों को रखने के बदले में पैसा वसूला जा रहा है। यानी गौशाला में मवेशियों का किराया लिया जा रहा है। बरेथा की गौशाला में सीमेंट की बोरियां भरी हैं और पनिहारी की गौशाला में मवेशियों के बजाय एक आदिवासी परिवार रह रहा है। गौरतलब है कि जिले में 28-28 लाख रुपए की लागत से निर्मित 29 गौशालाएं बनाई गई हैं। जिले की 29 गौशालाओं की हालात चौंकाने वाले है। मुरैना के जारौनी, सबलगढ़ की खिरका, बावडीपुरा, सिकरौदा, पहाड़गढ़ के कड़ावना, कुंअरपुर, अगरौता, बरेंड समेत जौरा की रूनीपुर व अलापुर गौशालाएं खाली पड़ी हैं। वहां गाय के नाम पर कोई पशु नहीं पाया गया। पशु चिकित्सा विभाग ने इन 10 गौशालाओं में दर्शाए गए 619 गौवंश के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक 8 लाख 35 हजार 650 रुपए का अनुदान जारी किया था।

पनिहारी में रह रहा परिवार

पनिहारी: गौशाला में एक भी पशु नहीं है, लेकिन अनुदान के लिए 67 पशुओं की टैगिंग कागजों में दिखाई जा रही है। यहां चारे, पानी व दाना का प्रबंध नहीं है। लेकिन इस गौशाला को अनुदान लगातार दिया जा रहा है। इस गौशाला में एक आदिवासी परिवार रह रहा है। गांव के पशु तालाब किनारे चारा चरने जाते हैं। साधु बाबा स्व-सहायता समूह के संचालक राजवीर जालौन का कहना है कि गौशाला में आदिवासी परिवार गायों की देखभाल के लिए यह रहा है। 67 पशुओं की टेगिंग के आधार पर इस गौशाला को दिसंबर 2023 में 90983 रुपए का अनुदान मिला है। उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. आरपीएस भदौरिया का कहना है कि स्थानीय पशु चिकित्सक की टेगिंग रिपोर्ट के आधार पर अनुदान जारी किया गया है।

छह गौशालाओं में भूखी गाय

मुरैना जिले की 6 गौशालाओं का मौके पर जाकर जायजा लेने पर गौवंश वहां तीन से चार तालों में बंद नजर आया। ऐसी गौशालाओं में मुरैना के चुरहला, धनेला, अंबाह के बरेथा, मलबसई व चांदपुर व पोरसा के सेंधरा बढ़ई शामिल हैं। गायों के लिए वहां भूसा नहीं था। इससे गौवंश बेहाल था। पानी का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं था।

सिंगारदे: किराए के गौवंश को गौशाला में भूसा-दाना नहीं मिल रहा है। दान में मिली बताकर पशु चिकित्सा विभाग से टैग लगवाए सिंगारदे की गौशाला में गांव का एक भी गया नहीं हैं। यहां पर दूसरे गांव के 99 गाय व 27 नंदी सखे ज रहे हैं। लेकिन इनके लिए गौशाला में भूसा और दाने का कोई इंतजाम नहीं है। बल्कि इसके बदले में सिद्ध बाबा स्व सहायता समूह को संचालिका कुसमा कुशवाह व सैनी शर्मा, भूरापुरा के चरवाहे रामनाथ यादव को 7-8 हजार रुपए महीना देती हैं।

अनुदान प्राप्त कर रही गौशालाओं में गायों को चेक कराया जाएगा। जहां अनुदान का दुरुपयोग प्रमाणित होगा ऐसे संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय की जाएगी।

-डॉ. इच्छित गढ़पाले, सीईओ जिला पंचायत, मुरैना

समूह संचालक ने बताया कि उसने रामनाथ यादव से गाय दान में ले ली है। इस गौशाला को इन गौवंश के नाम पर हर माह अनुदान जारी किया जा रहा है।

डॉ. महेंद्र कनेरिया, पशु चिकित्सक

हर साल निपानिया जाट और अगरिया में बनाए जाते थे गेहूं तुलाई केंद्र

तुलाई केंद्र बना दिया 35 किमी दूर, अब परेशान हो रहे दस गांव के 2000 किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

फंदा ब्लॉक के कुठार ग्राम सहित आसपास के 10 अन्य गांवों के किसानों को 135 किमी दूर जाकर अपनी उपज बेचना पड़ रही है। लंबी दूरी तय कर तुलाई केंद्र पर पहुंचने के कारण किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। नियमों के तहत 8 किमी की परिधि में उपज केंद्र होना चाहिए। किसानों से मिली जानकारी के बाद समस्या को जानने जब **जागत गांव हमार** ने बैरसिया विधानसभा के देवपुर, शाहपुर, कुठार और चंदेरी ग्राम का दौरा किया, तो लगभग सभी किसानों की फसल तुलाई के इंतजार में मिली।

किसानों ने बताया कि पिछले दो वर्षों से कुठार में तुलाई केंद्र का संचालन हो रहा था। इसके पहले 13 किमी दूर निपानिया जाट और अगरिया में उपार्जन केंद्र बनते थे। दूरी घटाने कुठार में केंद्र बनाया गया, लेकिन इस वर्ष शासन ने 35 किमी दूर मुगालिया कोट स्थित सायलो को उपार्जन केंद्र बनाया है। इससे फसल की बिक्री करने के लिए किसानों को 70 किमी का आवागमन करना पड़ रहा है। लंबी दूरी तय करने के कारण ऐसे किसान जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनकी जेब से 5 हजार रुपए तक खर्च हो रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली वाले किसानों को भी 3500 रुपए खर्च कर मुगालिया कोट पहुंचना पड़ रहा है। तुलाई केंद्र में नमी, मिट्टी, अन्य खाद्यान्न, सिकुड़े या टूटे हुए दाने अधिक होने पर फसल लौटाने से किसानों की लागत बढ़ रही है। बीते दो दिन में चमक विहीन गेहूं बताकर 10 से ज्यादा किसानों की फसल लौटा दी गई है। यह किसान 20 किमी की दूरी तय कर उपज केंद्र पहुंचे थे। इधर, बैरसिया विधायक विष्णु खत्री का कहना है कि मैंने आज भी कलेक्टर भोपाल को किसानों की इस समस्या से अवगत कराते हुए कुठार में उपार्जन केंद्र बनाने को कहा है। वहीं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि जिन गांवों को समस्या है, उनकी जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। उपार्जन केंद्र बढ़ा दिया जाएगा।

खुले में पड़ी गेहूं की फसल पर मंडरा रहा खराब मौसम का खतरा

जागत गांव हमार की टीम ने 10 से ज्यादा किसानों के घर पहुंचकर देखा तो सबकी फसलें खुले में पड़ी मिली। यदि बारिश होती है तो फसल की क्वालिटी खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं पूरे क्षेत्र में केवल 500 किसानों के पास ही ट्रैक्टर-ट्रॉली हैं। पास में उपार्जन केंद्र होने से बड़े किसान अपनी फसल बेचने के बाद अन्य किसानों को भी किराए पर ट्रॉली दे देते हैं। उपार्जन केंद्र दूर होने से एक ट्रॉली एक दिन में एक ही किसान की फसल को उपार्जन केंद्र तक पहुंचा पा रही है।

मप्र में समर्थन पर 92 फीसदी गेहूं की खरीदी, मध्य प्रदेश पिछड़ गए पंजाब और हरियाणा

मध्यप्रदेश का 8वां कृषि कर्मण अवॉर्ड पक्का!

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की सरकारी खरीद कागजों में एक अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन पंजाब और हरियाणा सहित कई सूबों में अभी किसान अपनी फसल बेचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गेहूं उत्पादक 10 राज्यों में से अभी तक सिर्फ पांच में ही खरीद हो रही है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट इसकी तस्दीक कर रही है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से मिली रिपोर्ट बता रही है कि अभी तक अप्रैल माह में देश भर में मात्र पौने आठ लाख मीट्रिक टन (7,74,759) की ही खरीद हो सकी है। जिसमें से 92 फीसदी से अधिक गेहूं मध्य प्रदेश में खरीदा गया है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं

उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश सेंट्रल पूल यानी बफर स्टॉक के लिए गेहूं का पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। अभी तक के गेहूं खरीदी के आंकड़ों से साफ जाहिर है कि मध्यप्रदेश का एक बार फिर कृषि कर्मण अवॉर्ड पक्का है। गौरतलब है कि मप्र अभी सात बार कृषि कर्मण अवॉर्ड हासिल कर चुका है। हालांकि अभी खरीदी चल रही है।

पंजाब-हरियाणा फिसड्डी-पंजाब बफर स्टॉक में सबसे ज्यादा गेहूं देता है, लेकिन वहां पर अभी खरीद ठीक से शुरू नहीं हो पाई है। ऐसा अनुमान है कि बैसाखी के बाद खरीद जोर पकड़ेगी। यही हाल हरियाणा का भी है। जहां एक अप्रैल से खरीद की कागजी घोषणा तो शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक न तो पूरी तरह से आवक हो रही है और न खरीदी। किसान मंडियों में गेहूं लेकर जा रहे हैं लेकिन उन्हें नमी की अधिक मात्रा बताकर लौटाया जा रहा है। एमएसपी पर गेहूं खरीद के लिए 12 फीसदी से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। इस साल सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2275 रु. क्विंटल तय किया है।

पिछले साल भी देरी से हुई थी खरीदी

पिछले साल भी हरियाणा की तमाम मंडियों में 10 अप्रैल तक गेहूं की खरीद नहीं शुरू हो पाई थी। किसान मंडियों में गेहूं सुखा रहे थे। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि कि इस बार गेहूं की कटाई में देरी है। अभी गेहूं पका नहीं है। नमी ज्यादा होने की वजह से ही अभी तक सरकारी खरीद ने जोर नहीं पकड़ा है।

किस राज्य में कितनी हुई गेहूं खरीद

राज्य	खरीद (मी.टन)
बिहार	179.16
हरियाणा	4,029.85
मध्य प्रदेश	7,15,327.74
राजस्थान	24,882.77
उत्तर प्रदेश	30,339.20

सरसों फसल का रकबा 100.39 लाख हेक्टेयर, एमएसपी से कम रेट पर बाजारों में बिक रही

किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने जिलों में तेल के लिए सरसों की उपज की प्रोसेसिंग की व्यवस्था जरूरी

सरसों उत्पादक किसानों को दो-तरफा मार पैदावार में कमी और दाम भी मिला रहा कम

भोपाल। जागत गांव हमार

पिछले साल खाद्य तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखकर और खाद्य तेल की बाजार में बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए किसानों ने इस साल सरसों की खेती अधिक रकबे में की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कि रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर सरसों फसल का रकबा 100.39 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के रिमोट सेंसिंग-आधारित अनुमान 95.76 लाख हेक्टेयर से पांच प्रतिशत अधिक है। लेकिन किसानों का कहना है कि इस साल प्रति किसान की पैदावार कम हो रही है, जिससे उन्हें सरसों की फसल में ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ, सरसों की उपज एमएसपी से कम दामों पर बाजार में बिक रही है, जिससे किसानों को काफी निराशा है। इस तरह, उनको दो तरफा नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार केवल खेती का रकबा बढ़ाने और उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देती है, लेकिन किसानों की रुचि जिस भी फसल में हो, उसके उचित मूल्य पर खरीदारी और हर जिले में तेल के लिए सरसों की उपज की प्रोसेसिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे किसानों को सरसों की खेती से फायदा होगा। किसानों का कहना है कि सरसों की खेती से किसान की आय में वृद्धि होगी, तो किसान सरसों की खेती में रुचि दिखाएंगे।

सरसों की पैदावार में कमी- राजस्थान के जयपुर किसानों का कहन है कि हमने इस असिंचित दशा वाले खेतों में इस साल 4 एकड़ में सरसों की फसल लगाई है। लेकिन इस साल कम बारिश के कारण सितंबर और अक्टूबर में खेतों में नमी ना रहने के कारण सरसों की बढ़वार और पैदावार कम हुई है। इस साल एक एकड़ में चार क्विंटल ही पैदावार हुई है, जबकि पिछले साल 6 क्विंटल पैदावार हुई थी। बेहतर दाम की आशा में सरसों की फसल लगाई थी, लेकिन अभी मार्केट में पीली सरसों का दाम 4600 से 4800 रुपए और काली सरसों 5000 रुपए क्विंटल बिक रही है, जबकि सरसों की एमएसपी 5660 रुपए प्रति क्विंटल है।

सरसों उत्पादक किसानों में भारी निराशा

मध्य प्रदेश के किसानों का कहना है कि हम सरसों की फसल लगाते हैं। इस साल सरसों की पैदावार 30 से 40 फीसदी तक गिरी है। एक महीने ज्यादा ठंड और कोहरे के कारण सरसों की पैदावार गिरी। जहां पहले प्रति एकड़ 8 से 9 क्विंटल पैदावार मिलती थी। वहीं इस साल 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ मिली है। इससे सरसों किसान काफी निराश हैं। हमारी उपज एमएसपी से कम दाम पर बिक रही है। अगर हमें सरसों का मूल्य स्थिर रखना है, सरसों की खेती पर ज्यादा जोर देना चाहिए। सरकार केवल खेती का रकबा बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर देती है, लेकिन किसानों को किसी भी फसल को बढ़ाना हो तो सरकार को उचित मूल्य पर खरीदारी करनी चाहिए। हर जिले में तेल के लिए सरसों की उपज की प्रोसेसिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। सरसों की खेती से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, तो किसान सरसों की खेती में और रुचि लेंगे। सरकार भी चाह रही है कि देश में तिलहन फसलों को खेती का रकबा बढ़े। पिछले साल खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरसों की खेती का रकबा किसानों ने बढ़ाया है, लेकिन पैदावार कम मिलने और बेहतर दाम ना मिलने से किसान काफी निराश हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार किसानों के पक्ष को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस कदम उठाए, जिससे किसानों की तिलहन फसलों की खेती में रुचि कम ना हो।

सरसों की खेती करें या नहीं

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के किसानों ने बताया कि हमने 10 एकड़ में सरसों की फसल लगाई है। पिछले साल इस समय बाजार में सरसों का दाम 6000 रुपए क्विंटल मिला था। लेकिन इस साल बाजार में 4800 रुपए क्विंटल का दाम मिल रहा है। जबकि सरकारी एमएसपी की कीमत 5660 रुपए है। हमारे जिले में एमएसपी पर सरसों की खरीदारी का कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है, जिससे बाजार में मजबूरी से बेचना पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में खराब मौसम के कारण इस साल सरसों की पैदावार में गिरावट आई है। पिछले साल प्रति एकड़ 10 क्विंटल पैदावार मिली थी, लेकिन इस बार 7 से 8 क्विंटल उत्पादन हुआ है। इससे सरसों के किसान को काफी नुकसान हो रहा है। सरकार हर साल कहती है कि किसानों को तिलहन की खेती बढ़ानी चाहिए, लेकिन अगर किसानों को लाभ नहीं मिलेगा तो सरसों की खेती क्यों करेंगे।

इन कारणों से उपज में कमी

कृषि विज्ञान केंद्र दतिया के प्रमुख और सरसों फसल के विशेषज्ञ डॉ. आरकेएस तोमर ने बताया कि इस साल सितंबर और अक्टूबर में कम बारिश के कारण खेतों में नमी नहीं थी। इसके कारण किसानों ने सरसों की बोवनी से पहले को पलेवा दिया। इसके परिणाम स्वरूप, सरसों की पैदावार कम हुई और जनवरी में कोहरे और पाला के कारण सरसों में रस्ट रोग लगा। इस साल सरसों की फसल की खेती के रकबे में काफी वृद्धि हुई है। सरकार भी तिलहन फसल की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। सरसों की प्रजातियों को जलवायु परिवर्तन के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि तापमान के उतार-चढ़ाव से सरसों की उपज प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन में सल्फर की कमी से भी सरसों की उपज प्रभावित होती है। किसानों को समय पर बुवाई के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि देरी से बोवनी से उपज में कीट और रोगों का प्रकोप होता है। सरसों की देशी किस्मों को विकसित करना भी जरूरी है। सरसों को सबसे लाभकारी मूल्य के साथ स्थिर रखना चाहिए, ताकि किसानों को लाभ मिले और उन्हें सरसों की खेती में रुचि बनी रहे।

आटा मिल संगठन ने उत्पादन अनुमान आंकड़े किए जारी

देश में गेहूं का उत्पादन 105 मिलियन मीट्रिक टन का अनुमान

आटा मिल संगठन का अनुमानः बीते साल गेहूं सरकारी अनुमान से 10 फीसदी कम था

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में 2024 सीजन में गेहूं उत्पादन का सरकारी आंकड़ा 112 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि आटा मिल संगठन ने गेहूं उत्पादन अनुमान आंकड़े जारी किए हैं। जिसके अनुसार सरकारी अनुमानों से 6.25 फीसदी कम उपज होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में सरकारी खरीद टारगेट को झटका लग सकता है। देशभर में अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है और इस बार सरकारी भंडार भरने के लिए सहकारी समितियों को भी खरीद में लगाया गया है। आटा मिलों के संगठन ने कहा है कि भारत में इस साल 105 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो सरकारी अनुमान से 6.25 फीसदी कम है। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष नवनीत चितलांगिया ने कहा कि देशभर में फसल का आकलन करने के बाद हमारा मानना है कि इस साल गेहूं का उत्पादन 105 मिलियन मीट्रिक टन होगा।

बीते साल 10 फीसदी कम हुआ गेहूं

सरकारी अनुमान के मुताबिक भारत में 2024 में 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 112.74 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया, लेकिन व्यापार और उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल गेहूं का उत्पादन सरकार के अनुमान से 10 फीसदी कम था। गेहूं के कम उत्पादन ने सरकार को अपने भंडार से आटा मिलों और बिस्किट निर्माताओं जैसे थोक खरीदारों को रिकॉर्ड 10 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं बेचने के लिए मजबूर किया, जिससे दुनिया के सबसे बड़े खाद्य कल्याण कार्यक्रम के लिए आवश्यक भंडार में कमी आई है। मार्च की शुरुआत में सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार घटकर 9.7 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जो 2017 के बाद से सबसे कम है।

एफसीआई 6 मिलियन टन अधिक खरीद रही गेहूं

एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक केके मीना ने कहा कि एफसीआई को 2023 में 26.2 मिलियन मीट्रिक टन के मुकाबले इस साल घरेलू किसानों से 31-32 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं खरीदने की उम्मीद है। एफसीआई ने पहले ही नए सीजन का गेहूं खरीदना शुरू कर दिया है, अप्रैल की शुरुआत में मौजूदा फसल सीजन की शुरुआत के बाद से घरेलू किसानों से दस लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 700,000 मीट्रिक टन था।

सहकारी समितियों को खरीद में लगाया

केंद्र सरकार ने गेहूं के पर्याप्त स्टॉक करने के लिए वैश्विक और घरेलू व्यापार घरानों को स्थानीय किसानों से नए सीजन का गेहूं खरीदने से रोक दिया है। इससे सरकार किसानों का गेहूं खरीद कर अपने घटते भंडार को बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। इस बार एफसीआई के अलावा नेफेड और एनसीसीएफ को भी गेहूं खरीद के लिए सरकार ने लगाया है।

भारत में मवेशियों में लम्पी त्वचा रोग के पीछे वायरस के कई वेरिएंट

मई 2022 में, भारत भर में मवेशी एक रहस्यमय बीमारी से मरने लगे थे। तब से, लगभग 1,00,000 गायें इसके विनाशकारी प्रकोप से अपनी जान गंवा चुकी हैं, वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान लम्पी या गांठदार त्वचा रोग के रूप में की। इस प्रकोप ने भारत के कृषि क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अध्ययन में शोधकर्ता ने कहा कि यह कुछ मायनों में एक आपदा थी, जिसे एक राष्ट्रीय आपातकाल भी कह सकते हैं। शोधकर्ता उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने प्रकोप के कारण की जांच करने का निर्णय लिया।

लंपी बायरस के बारे में वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया। यह अध्ययन इस रोग को फैलाने वाले वायरस और उनके वेरिएंटों के विकास और उत्पत्ति में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

बीएमसी जीनोमिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) के कारण होने वाला एक संक्रामक संक्रमण, यह बीमारी मक्खियों और मच्छरों जैसे कीड़ों से फैलती है। यह बुखार और त्वचा पर गांठों का कारण बनता है और मवेशियों के लिए घातक हो सकता है।

लम्पी त्वचा रोग पहली बार 1931 में जाम्बिया में पाया गया था और 1989 तक उप-अफ्रीकी क्षेत्र तक ही सीमित रहा, जिसके बाद दक्षिण एशिया में फैलने से पहले यह मध्य पूर्व, रूस और अन्य दक्षिण-पूर्व यूरोपीय देशों में फैलना शुरू हो गया। भारत में इस बीमारी के दो बड़े प्रकोप हुए, पहला 2019 में और दूसरा 2022 में अधिक गंभीर प्रकोप, जिसने 20 लाख से अधिक गायों को संक्रमित किया।

वर्तमान प्रकोप की जांच करने के लिए, टीम ने पशु चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में संक्रमित मवेशियों से त्वचा की गांठें, रक्त और नाक के नमूने एकत्र किए। उन्होंने 22 नमूनों से निकाले गए डीएनए की उन्नत संपूर्ण-जीनोम अनुक्रमण का प्रदर्शन किया।

अध्ययन में शोधकर्ता बताते हैं, सबसे बड़ी चुनौती एक स्थापित लम्पी त्वचा रोग वायरस जीनोम अनुक्रमण और विश्लेषण की कमी थी। अध्ययनकर्ताओं को कोविड-19 शोध के तकनीकों को अपनाना पड़ा। आंकड़े भी सीमित थे, इसलिए शोधकर्ताओं ने अध्ययन के हवाले से बताया कि अपने विश्लेषण को मजबूत बनाने के लिए सभी उपलब्ध वैश्विक लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) जीनोम अनुक्रमों को जमा किया। अध्ययन के मुताबिक, जीनोमिक विश्लेषण से पता चला कि भारत में दो अलग-अलग एलएसडीवी वेरिएंट घूम रहे हैं, एक कम संख्या में आनुवंशिक विविधता वाला और दूसरा अधिक संख्या में आनुवंशिक विविधता वाला। कम विविधताओं वाला अनुक्रम आनुवंशिक रूप से 2019 रांची और 2020 हैदराबाद में पाए गए वेरिएंट के समान था जिन्हें पहले अनुक्रमित किया गया था। हालांकि, उच्च विविधता वाले नमूने 2015 में रूस में फैलने वाले एलएसडीवी वेरिएंटों के समान निकले।

अध्ययन में कहा गया है कि भारत में इस तरह के अत्यधिक विविध एलएसडीवी वेरिएंटों की कोई पिछली रिपोर्ट नहीं है। जिन वायरसों में आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए होता है, जैसे एलएसडीवी वे आमतौर पर आरएनए वायरस की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। इसलिए, इतनी सारी आनुवंशिक विविधताएं ढूंढना काफी कठिन था जिससे बीमारी की गंभीरता को समझा जा सके।

अध्ययन में कहा गया है कि टीम को बड़ी संख्या में आनुवंशिक विविधताएं मिलीं जो 1,800 से अधिक थी। इनमें विभिन्न जीनों में विलोपन और सम्मिलन, डीएनए में एकल-अक्षर परिवर्तन (एसएनपी कहा जाता है) और जीन के बीच के क्षेत्रों में आनुवंशिक भिन्नताएं शामिल हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने संक्रमित जीन में बड़ी संख्या में आनुवंशिक विविधताएं पाई जो पशु कोशिकाओं से जुड़ने, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बचने और कुशलतापूर्वक अपने आप को दोगुना करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे हो सकता है वायरस की बीमारी पैदा करने की क्षमता बढ़ गई।

अध्ययन में शोधकर्ता ने कहा मवेशियों में उन क्षेत्रों में अधिक गंभीर लक्षण विकसित हुए जहां अत्यधिक विविध नस्लें थी। इससे पता चलता है कि आनुवंशिक विविधताएं विषाणु को बढ़ा सकती हैं।

इस तरह की जानकारी पशुधन और आजीविका को खतरे में डालने वाली उभरती संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए बेहतर जांच, टीके और हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। शोध टीम ने महामारी के दौरान कोविड??-19 पर और हाल ही में रेबीज वायरस पर इसी तरह के अध्ययन किए हैं।

अध्ययन के मुताबिक, जीनोमिक आंकड़े आणविक हॉटस्पॉट और लक्ष्य के लिए आनुवंशिक विविधताओं को प्रकट करके वैक्सीन विकास के लिए अहम साबित होगा। यह राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रकोप के दौरान एलएसडीवी के जीनोमिक परिदृश्य को चित्रित करने वाला पहला मामला है।

अध्ययन में कहा गया है कि यह वन हेल्थ दृष्टिकोण का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें आणविक जीव विज्ञानी, कम्प्यूटेशनल विशेषज्ञ और पशु चिकित्सा डॉक्टरों सहित अलग-अलग विषयों की टीमें राष्ट्रीय प्रासंगिकता के मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ आती हैं।

अध्ययन में शोधकर्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश भर में वेरिएंट का पता लगाने के लिए पशु चिकित्सा विशेषज्ञों और कई वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था। अध्ययन के हवाले से शोधकर्ता ने यह भी बताया कि उन्होंने पशु चिकित्सकों से बहुत कुछ सीखा। वे स्थानीय ज्ञान को समझते हैं और बीमारी के बारे में उनकी धारणा बहुत महत्वपूर्ण थी।

अधिक उत्पादन के लिये करे बैंगन की वैज्ञानिक खेती

» डा. विशाल मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक
» डॉ. ब्रजकिशोर प्रजापति (सस्य विज्ञान)
» डॉ. आशुतोष शर्मा (कृषि वानिकी)
» डॉ. एस.आर. शर्मा (पौध सरंक्षण)
» डॉ. निधि वर्मा (सस्य विज्ञान)
» डॉ. विजय सिंह सूर्यवशी
कृषि विज्ञान केन्द्र, नरसिंहपुर

बैंगन अर्थात भटा एक प्रमुख शाक फसल हैं, जो कि वर्ष भर बाजार में बहुतायत से उपलब्ध रहती है एवं सभी वर्गों के लोगों द्वारा पंसद की जाती है। इसका आयुर्वेद औषधि में भी प्रयोग किया जाता है। इसे सब्जियों का राजा भी कहते हैं । बैगन एक ओर सत्ता तथा दूसरी ओर हमेशा उपलब्ध रहने वाली सब्जी है। यदि बैगन की खेती वैज्ञानिकों के अनुसार की जाए तो बैगन की फसल किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने बैगन की कई नई किस्में भी तैयार की हैं, जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है।

बैंगन की खेती के लिये हल्की से मध्यम श्रेणी की भूमि हो एवं जिसमें जल निकास उत्तम हो। पी.एच. 5.5 से 6.8 के बीच हो।

भूमि की तैयारी: पौधरोपण के पहले खेत में लगभग 200 विंवटल गोबर की खाद, फास्फेट एवं पोटाश की पूरी एवं नत्रजन की आधी मात्रा का भुरकाव कर दो से तीन बार अच्छी तरह जुताई करें और भूमि को समतल बनाएं।

उन्नत किस्में: देश भर के बैंगन की दर्जनों किस्में उपलब्ध हैं प्रयोगों के आधार पर हमारे क्षेत्र के लिये जो उत्तम पायी गई है, जो इस प्रकार है।

जवाहर बैंगन 64 एवं 15, पूसा परपल लांग, पूसा परपल क्लस्टर, पंत सम्राट, पंत ऋतुरात, पूसा क्रांति, काशी तरू, काशी संदेश, काशी कोमल एवं काशी प्रकाश, अर्का केशन, अर्का कुसुमकर, अर्का नवनीत, अर्का शील, अर्का सीरिस आदि।

बैगन की संकर किस्में: बैंगन की उन्नत किस्मों की तुलना में संकर जातियाँ कुछ बातों में भिन्न हैं जैसे बीज की मात्रा अंतराल खाद की मात्रा एवं फलों का वजन आदि।

संकर किस्में: *हर्षिता, निशा, छाया, कल्पतरू, रवैया, सुफल, एम.एच.बी, 80, एम.एच.बी. 82 एवं एम.ई.वी. एच.11, अंतराल - 90 से.मी पंक्ति से पंक्ति ग 60 से.मी. पौधे से पौधे की दूरी।*

फसल चक्र: फसल चक्र अपनाकर सहज में ही अनेक रोग एवं कीट नियंत्रित किये जा सकते हैं। बैंगन के लिये यह चक्र ऐसा हो:-

क्र.	रबी	जायद	खरीफ
1	मटर	बैंगन	भिंडी
2	बैंगन	बरबटी	मिर्च
3	बैंगन	भिंडी/बरबटी	बैंगन

बीज की मात्रा: विभिन्न किस्मों के लिये बीज की मात्रा 500 से 600 ग्राम/हे. आवश्यक है।

लगाने का समय: 1. वर्षा की फसल: जुलाई अगस्त में रोपण। **2. गर्मी की फसल:** जनवरी-फरवरी में रोपण कही कही, पर मार्च अप्रैल में रोपण किया जाता है।

रोपणी तैयार करना: मुख्य खेत में रोपाई के लगभग 1 से 2 माह पूर्व बीज की पौधशाला में बोवाई करना आवश्यक है। एक हेक्टेयर के लिये इस तरह लगभग 25 क्यारियां लगेंगी। बीज बोवाई के पूर्व उपचार अवश्य करें।

भूमि उपचार: फार्मेल्डिहाइड दवा, 10 मि.ली. प्रति लीटर पानी अथवा कापर सल्फेट दवा, 100 ग्राम प्रति 50 लीटर पानी में घोलकर तैयार क्यारियां की मिट्टी पर छिड़के एवं मिट्टी व गोबर की खाद के साथ अच्छी तरह मिलाएं।

वर्षा ऋतु में फसल लेने के लिये एक विधि और अपनायी जा सकती है जिसे सोलोराईजेशन कहते हैं इसमें भूमि का उपचार मई माह की तेज धूप में गोबर की खाद देकर पानी से तर करते हैं एवं लगभग 200 गेज की पारदर्शी पॉलीथीन से इस तरह ढंकते हैं कि अन्दर की हवा बाहर न निकल सके। दो सप्ताह बाद उपचारित भूमि को भुरभुरा करें एवं उपचारित बीज की पंक्तियों में बोवाई करें।

बीजोपचार: भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिये बीजोपचार किया जाना अति आवष्यक प्रक्रिया है। इसमें कार्बेन्डाजिम् (12:) .मेंकोजेब (63:) दवा की मात्रा 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से प्रयोग करना चाहिये ।

क्यारियों का रख रखाव: क्यारियों को मल्च (पेरा घास अथवा पत्तों) से ढककर नियमित रूप से सिंचाई करें। लगभग एक सप्ताह बाद मल्च हटा दें। पौधों को खुले रूप से बढ़ने दें एवं जब 6 से 7 सप्ताह के हो जावें तो मुख्य स्थान पर रोपाई करें।

पौधों की रोपाई: स्वस्थ तैयार पौध को पूर्व से तैयार खेत में 60 से.मी. कतार से कतार एवं 45 से.मी. पौधे से पौधे की दूरी पर लगावे ध्यान रहे कि पौध रोपण के समय भूमि में कुछ नमी रहें।

खाद एवं उर्वरक की मात्रा: बैगन में भरपूर पैदावार लेने के लिये यह आवश्यक है कि पौधों को पर्याप्त पोषण मिले। औसतन प्रति हेक्टेयर 200 विंवटल गोबर की खाद, 100 किलो ग्राम नत्रजन, 50 किलो ग्राम स्फुर एवं, 50 किलो ग्राम पोटाश आवश्यक है। भूमि तैयारी के बाद बची नत्रजन फल तुड़ाई के बाद दें।

पौध संरक्षण-प्रमुख कीट एवं रोकथाम

1. फलों की इल्ली इस कीट का प्रकोप काफी अधिक होता है। इल्ली कच्चे एवं पके फलों को छेद कर नुकसान पहुँचाती हैं।

रोकथाम: ट्राईजोफास 40 ई.सी. या नुवान (2 मि.ली. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।

एपिलेक्ना बीटल: इसके शिशु एवं वयस्क कीड़े पत्तियों को खाकर जालीनुमा बना देते हैं। इल्ली एवं प्रौढ दोनों ही अवस्था में नुकसान पहुँचाते हैं।

रोकथाम: फूल आने से पहले सेविन का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।

एफिडस, जैसिड एवं सफेद मक्खी: इसमें कीट बहुत ही छोटे होते हैं ये पत्तियों का रस चूसते हैं।

रोकथाम: कीटों की रोकथाम हेतु थायोमेथाक्सॉम 0.4 ग्राम या इमिडाक्लोरप्रिड 0.5 मिली या एसिडामाप्राईड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दवा का छिड़काव दो सप्ताह के अन्तराल पर करें। नीम तेल 5 मि.ली./लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

तना एवं फल छेदक: इस कीड़े की इल्लियाँ बैंगन के फलों एवं पौधों को हानि पहुँचाती हैं। ये इल्लियाँ पौधों को अन्दर से खाती रहती है। पौधों की पत्तियाँ एवं तने सूख जाते हैं छेद किये गये स्थान पर कीटों का मल स्पष्ट दिखाई देता हैं।

रोकथाम के लिये: रोग ग्रस्त पौधे के भाग को काट कर अलग कर दें। कीट प्रतिरोधी किस्में पंत सम्राट, पूसा कांति, जे.बी. 64 को लगायें। ट्राईजोफास 40 ई.सी. (2.5 मि.ली./ लीटर पानी) का छिड़काव करें।

हरियाणा-राजस्थान में घटेगा कपास का रकबा, किसानों ने बनाई दूरी!

उत्तर भारत में खरीफ कपास की बुआई शुरू हो गई है। लेकिन इस बार इसके रकबे में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछले सीजन में कपास की फसल में पिंक बॉलवर्म नामक बीमारी फैल गई थी। इसके चलते कपास की क्वालिटी प्रभावित हुई और कीमतों में गिरावट देखी गई। ऐसे में किसानों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस साल नुकसान से बचने के लिए बहुत से किसानों ने कपास की खेती से दूरी बना ली। वे इस साल धान, मक्का और ग्वार की खेती करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इनकी खेती में कपास के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा।

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन में बीज व्यवसाय के सीईओ सत्येन्द्र सिंह ने कहा कि पिंक बॉलवॉर्म एक गंभीर संक्रमण है। इसके चलते उपज तो प्रभावित होती ही है, साथ में किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन में कपास की बुआई की शुरुआत धीमी है, क्योंकि बीज की बिक्री भी कम हो रही है। पिछले साल इस समय तक कपास के बीच की खूब बिक्री हुई थी। हालांकि, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुल कपास के रकबे जानने के लिए हमे इंतजार करना होगा होगा। उन्होंने कहा कि तीनों उत्तरी राज्यों में कपास का रकबा पिछले साल के स्तर को नहीं छू पाएगा।

जोधपुर में साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (एसएबीसी) के संस्थापक निदेशक भागीरथ चौधरी ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान के किसान इस साल कपास के रकबे को कम करने के लिए पंजाब का रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि पीबीडब्ल्यू के गंभीर संक्रमण ने फसल की गुणवत्ता पर असर डाला है। इसके अलावा, खराब गुणवत्ता के कारण आय पर असर पड़ा और किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला।

चौधरी ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान में कपास के रकबे में लगभग 25 प्रतिशत की कमी आ सकती है और पंजाब में भी मामूली गिरावट देखी जा सकती है। पंजाब के उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता है, किसान वापस धान की खेती की ओर लौट सकते हैं, जबकि राजस्थान में वे ग्वार की ओर रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मक्का और मूंग भी एक विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। सिरसा में बीज खुदरा विक्रेता योगेश कुमार ढाका ने कहा कि रकबा लगभग 15 प्रतिशत कम हो जाएगा। पिछले साल की तुलना में कपास के बीजों की बिक्री धीमी है और किसानों ने उन क्षेत्रों में बुआई शुरू कर दी है जहां सरसों की कटाई हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता है, वहां किसान धान की खेती करेंगे।

सेब की खेती में स्विट्जरलैंड का मुकाबला करने को तैयार भारत

भारत ने सेब की खेती में हासिल की बड़ी कामयाबी

उपलब्धि: हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता

कृषि वैज्ञानिकों ने उत्पादन बढ़ाने का नया फॉर्मूला निकाला, विदेशी किस्मों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए देसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विकसित की

भोपाल। जागत गांव हमार

भले ही भारत दुनिया भर में बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी उत्पादकता के मामले में अभी हम कई फसलों में बहुत सारे देशों और विश्व औसत से काफी पीछे हैं। सेब इनमें से एक है। सेहत के लिए बेहद गुणकारी होने की वजह से सेब लगभग हर देश में उगाया जाता है। लेकिन जलवायु से जुड़ी परिस्थितियों और तकनीक की वजह से कुछ देश दूसरों की तुलना में बहुत अधिक सेब का उत्पादन करते हैं और कुछ बहुत कम। भारत की बात करें तो हम लोग इसकी उत्पादकता में बहुत पीछे हैं। यहां तक की विश्व औसत के भी आसपास नहीं हैं। लेकिन अब श्रीनगर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेंपरेट हॉर्टिकल्चर ने दुनिया में सेब की उत्पादकता के मामले में नंबर वन स्विट्जरलैंड का मुकाबला करने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले का सीआईटीएच कैंपस में ट्रॉयल भी हो चुका है, जिसमें भारत को सेब की खेती में 60 टन तक की उत्पादकता मिली है। अब इस मंत्र को आम किसानों के खेतों तक ले जाना है, ताकि उत्पादकता में बहुत पीछे रहने की बात करने वाले देशों के मुंह पर ताला लग जाए। एक तरफ हमारे यहां सेब की उत्पादकता सिर्फ 8.87 टन प्रति हेक्टेयर है तो वहीं इस मामले में 60.05 टन प्रति हेक्टेयर के साथ स्विट्जरलैंड दुनिया में नंबर वन है। विश्व औसत 17.56 टन है।

किसानों को मिलेगा फायदा

कृषि वैज्ञानिकों ने उत्पादन बढ़ाने का नया फॉर्मूला निकाला है। इसके तहत विदेशी किस्मों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए देसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विकसित की है। यह सेब की खेती में सबसे बड़ी क्रांति होगी, जिससे अंततः किसानों को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। उत्पादकता बढ़ने का मतलब है कम जगह में ज्यादा उत्पादन ले लेना। सीआईटीएच यानी केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान के डायरेक्टर डॉ. एमके वर्मा ने बताया कि सेब की वर्तमान में प्रचलित विदेशी किस्मों को ही वैज्ञानिकों ने उसकी खेती की तकनीक बदलकर उत्पादकता बढ़ाने का काम किया है।

राज्य	रकबा (हे.)	उत्पादन (मीट्रिक टन)	उत्पादकता (टन/हे.)
जम्मू-कश्मीर	1,68,570	18,9,859	11.26
हिमाचल प्रदेश	1,15,020	6,11,900	5.32
उत्तराखंड	25,980	64,880	2.50
अरुणाचल	4,440	6,830	1.54
नागालैंड	240	1,780	7.41

किसानों को मिलेगा ज्यादा मुनाफा

वर्मा ने बताया कि हम नई तकनीक में सेब के पेड़ की लंबाई मैकेनिकली कंट्रोल करते हैं। पौधों को वायर और लकड़ी का सपोर्ट देते हैं। इस तरह पौधों की ऊंचाई 12 से 14 फुट तक पहुंच जाती है। यह कमाल की तकनीक है, जिसे कोई भी किसान अपना सकता है। इस तकनीक से हमने 60 टन प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार ली है। अब भारत में सेब की खेती किसानों को पहले से अधिक मुनाफा देगी।

भारत में सेब का उत्पादन

- सीआईटीएच ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि साल 2021-22 के दौरान भारत में 315000 हेक्टेयर में सेब की खेती हो रही थी। जबकि कुल उत्पादन 2589000 मीट्रिक टन हुआ था।
- भारत सेब का आयातक है। ऐसे में अब नई तकनीक से उत्पादकता बढ़ेगी तो आयात पर निर्भरता कम होगी। हम भूटान तक से सेब मंगाते हैं। अमेरिका बड़े पैमाने पर अपने यहां पैदा वाशिंगटन एप्पल भारत भेजता है।
- जहां दुनिया का सबसे बड़ा सेब उत्पादक चीन है। वहीं भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक जम्मू कश्मीर है। दूसरे नंबर पर हिमाचल फिर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है।

भारत ब्रांड चना दाल सप्लाई के लिए चने की जरूरत

अब सरकार समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर खरीदेगी चना

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार किसानों से सीधे चना की खरीद करने की तैयारी कर रही है। बफर से नीचे गिरे स्टॉक को बढ़ाने के लिए सरकार मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत बाजार कीमत पर सीधे किसानों से चना खरीदेगी। ऐसे में किसानों को एमएसपी से करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दाम मिलने की उम्मीद है। भारत ब्रांड चना दाल सप्लाई के लिए केंद्र को चना की जरूरत है। देश में कुल दालों के उत्पादन में लगभग 50 फीसदी हिस्सेदारी चना की दाल की होती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान चना की बाजार कीमतें एमएसपी के मुकाबले करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल अधिक हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन में गिरावट की आशंका के कारण चना की वर्तमान बाजार कीमतें 5900-6000 रुपए क्विंटल के बीच चल रही हैं। जबकि, 2024-25 सीजन के लिए चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी रेट 5440 प्रति क्विंटल है।

खरीद टारगेट से पीछे नेफेड

अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बाजार कीमतों पर किसानों से सीधे खरीदारी करके सरकार बफर स्टॉक बढ़ाने की तैयारी में है। वर्तमान में चने की ऊंची कीमतों के कारण सहकारी संस्था नाफेड और राज्य स्तरीय एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एमएसपी खरीद नहीं कर पा रही हैं। मार्केटिंग सीजन अप्रैल-जून में नेफेड दस लाख टन लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 13,000 टन चना ही खरीदा पाया है। नेफेड ने 2023-24 में पीएसएस के तहत 2.3 मीट्रिक टन और 2022-23 सीजन में 2.6 मीट्रिक टन चना खरीदा था, जिससे बफर स्टॉक को बढ़ावा मिला था।

ब्रांड दाल के लिए खरीद की तैयारी

अधिकारियों ने कहा कि पिछले दो मार्केटिंग सत्रों में मजबूत खरीद ने पिछले साल बफर स्टॉक को 3 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया था। इससे सरकार खुले बाजार में चना बेचने के साथ ही भारत ब्रांड चना दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच सकी है। चने का बफर स्टॉक वर्तमान में एक मीट्रिक टन के मानक के मुकाबले लगभग 0.7 मीट्रिक टन तक गिर गया है। अब सरकार को भारत ब्रांड चना दाल के लिए भी चना की जरूरत है। ऐसे में बफर स्टॉक को बढ़ाने के लिए सरकार मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत बाजार दर पर किसानों का चना खरीदने की तैयारी कर रही है।

टमाटर की वैज्ञानिक खेती अपनाकर बढ़ाएं आमदनी

डॉ. विशाल मेश्राम
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक
कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर
डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव
वैज्ञानिक (कृषि अभियांत्रिकी)
डॉ. निधि वर्मा
वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान)
डॉ. एस.आर. शर्मा
वैज्ञानिक (पौध सरंक्षण)
डॉ. आशुतोष शर्मा
वैज्ञानिक (कृषि वानिकी)
डॉ. विजय सिंह सूर्यवशी
कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

टमाटर वर्ष भर उगाया जा सकता हैं। इसका उत्पादन करना बहुत सरल हैं। टमाटर का उपयोग सब्जी सूप ,सलाद, अचार ,केचप, फ्यूरी, एवं सास बनाने में किया जाता हैं। यह विटमिन एबी और सी. का अच्छा स्त्रोत हैं। इसके उपयोग से कब्ज दूर होता है।

भूमि का चुनाव- बलुई-दुमट मिटटी जिसमें जल निकास अच्छा हो टमाटर की खेती के लिऐ उपयुक्त होती हैं। भूमि का पी.एच.मान 6 से 7 तक होना चाहिए।

भूमि की तैयारी- दो या तीन बार जुताई करने के बाद बखर चलाकर मिटटी को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लेना चाहिये।तथा पाटा लगाकर खेत को सममतल बना लेना चाहिए।

जातियां- लक्ष्मी 5005, सुपर लक्ष्मी, काशी अमृत, काशी अनुपम, काशी विशेष, पुसा सदाबहार, अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आभा, अर्का विशाल, जवाहर टमाटर-99,

फसल चक्र

भिंडी -टमाटर - खीरा, बरबटी-टमाटर -करेला, खीरा -टमाटर -लौकी, बीज एवं बीजोपचार। टमाटर का बीज 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। नर्सरी में बीज बोने के पूर्व थायरम या डायथेन एम-45 नामक 3 ग्राम दवा की प्रति किलो ग्राम के बीज की दर से उपचारित करें।

रोपणी तैयार करना- पौधशाला की मिट्टी को कीटाणु एवं रोगाणु रहित करना अति आवश्यक है। इसके लिये क्यारियों को सौर ऊर्जा से उपचारित करें। इसमें तैयार क्यारियो (3.5 मी. ग. 1.0 मी.) को पोलीथिन शीट से ढंककर करीब 20 से 25 दिन तक रखें। बोवानी के 10 दिन पहले प्रत्येक क्यारियों में 10-20 किलो ग्राम अच्छी सड़ी गोबर की खाद तथा 500 ग्राम 15:15:15 सकुल उर्वरक डालिये। नर्सरी क्यारियों में कतार से कतार 10 सेमी. और बीज की दूरी 5 सेमी. (कतार में) रखते हुये एक इंच की गहराई पर बीज को बोएं। बोवानी के बाद क्यारियों को कांस अथवा सूखे पुआल से ढंक दे। इसके तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए। आवश्यतानुसार सिंचाई और पौध संरक्षण करते रहना चाहिए।

पौध रोपाई - अच्छी तरह तैयार खेत में सांयकालीन समय में कतार से कतार 60 सेमी. तथा पौधे से पौधे 30-45 सेमी. दूरी रखते हए रोपाई करें तथा सिंचाई करें।

खाद एवं उर्वरक - 200-250 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद 50 किलो स्फुर तथा 50 किलो पोटाश प्रति हेक्टर की दर से खेत की तैयारी करते समय डाल देना चाहिए। नत्रजन 100 किलो जिसकी एक तिहाई मात्रा पौधा लगाने के पूर्व तथा बाकी दो तिहाई पौधा लगाने के बाद दो बार में 20 दिन तथा 40 दिन बाद डालना चाहिए। वर्षा ऋतु में नत्रजन की पूरी मात्रा पौधे लगाने के बाद दो बार में 15 दिन तथा 45 दिन बाद डाल देना चाहिए।

सिंचाई - टमाटर की फसल में आवश्यकता होने पर हल्की सिंचाई करें, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठंड के दिनों 10-12 दिनों के अंतर से तथा गर्मी में 5-6 दिनों के अतंराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि पाला पड़ने की संभावना हो तो खेत की आवश्यक रूप से सिंचाई करें।

निदाई गुड़ाई - खेत को खरपतवारों से साफ रखने तथा फसल वृद्धि के लिये निंदाई गुड़ाई आवश्यक है। परन्तु यह गुड़ाई करते समय ध्यान रखे कि गुड़ाई उथली हो जिससे पौधे की जड़ों को नुकसान न हो। रासायनिक नीदा नियंत्रण के लिए लासों ईसी 50 का 4 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी मिलाकर रोपाई के दो दिन पूर्व छिड़काव करें। इस रसायन का प्रभाव केवल 45 दिन तक ही रहता है।

अन्य कार्य- बरसात मे फलों को सड़ने से बचाने के लिये पौधों को बांस या लकड़ी के सहारे जमीन से ऊपर रखें। पत्तियों पर कैल्सियम अथवा मैग्नीशियम सल्फेट के 0.3 प्रतिशत छिड़काव करने से फल कम फटते हैं। छिड़काव पौधे लगाने के एक महीने बाद दो बार 15 दिन के अंतर से करना चाहिए।

पौध संरक्षण कीट

फलों की इल्ली- इस कीट का प्रकोप काफी अधिक होता हैं। इल्ली कच्चे एवं पके फलों को छेद कर नुकसान पहुंचाती हैं।

रोकथाम के लिए - ट्राईजोफास 40 ई.सी. या नुवान (2 मिली प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।

2 एपिलेक्ना बीटल- इसके शिशु एवं वयस्क कीड़े पत्तियों को खाकर जालीनुमा बना देते हैं। इल्ली एवं प्रौंढ दोनों ही अवस्था में नुकसान पहुंचाते हैं।

रोकथाम के लिए- फूल आने से पहले सेविन का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।

3 एफिडस, जैसिड एवं सफेद मक्खी - इसमें कीट बहुत ही छोटे होते हैं ये पत्तियों का रस चूसते हैं।

रोकथाम के लिए- कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथाक्सॉम 0.4 ग्राम या इमिडाक्लोरप्रिड 0.5 मिली या एसिडामाप्राईड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दवा का छिड़काव दो सप्ताह के अन्तराल पर करें। नीम तेल 5 मिली /लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

4 तना एवं फल छेदक- टमाटर में इससे अधिक नुकसान होता है। इस कीड़े की इल्लियां टमाटर के फलों एवं पौधों को हानि पहुंचाती हैं। ये इल्लियां पौधों के तनों और बड़ी पत्तियों की मध्य शिराओं से प्रवेश करती है और उन्हें अंदर से खाती रहती हैं। पौधों की पत्तियां एवं तने सूख जाते हैं छेद किए गए स्थान पर कीटों का मल स्पष्ट दिखाई देता हैं। कीट फलों में छेदकर अंदर प्रवेश कर फलों को खाते हैं, जिससे फल खाने योग्य नही रहते।

रोकथाम के लिए- रोग ग्रस्त पौधे के भाग को काट कर अलग कर दें। ट्राईजोफास 40 ई.सी. (2.5 मिली/लीटर पानी) का छिड़काव करें।

5 थ्रिप्स- वह छोटे-छोटे कीट पत्तियाँ एवं अन्य मुलायम भागों से रस चूसते है। इसका प्रकोप रोपाई के 2 से 3 सप्ताह बाद शुरू हो जाता है। फूल लगते समय प्रकोप अधिक होता है।

खेती को लाभ का धंधा बनाएं

फसलों की नरवाई को ना जलाएं मिट्टी को नष्ट होने से बचाएं

छतरपुर। जागत गांव हमार

अभी हाल में गेंहू, जो (जवा) या अन्य किसी भी की फसल की कटाई हो चुकी है। मध्यप्रदेश या सम्पूर्ण भारत में अधिकतर किसान भाई हार्वेस्टर से कटाई करते हैं। जो डंठल होता है या फसल का अवशेष 90 प्रतिशत भाग बच जाता है उसको हम नष्ट करने के लिए अपने ही खेत में आग लगा देते हैं। आग लगाना खेत में कितना घातक होता है आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आग लगा देने से जमीन में लाखों करोड़ों सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जो की मिट्टी को बनाने में सहायक का कार्य करते हैं या मिट्टी को बनाने में मदद करते हैं। साथ ही मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, मिट्टी की ऊपरी परत में बिधमान होती है, वह भी सारी की सारी नष्ट हो जाती है। आपको पता नहीं है कि 1 इंच मिट्टी के बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन हम लोग क्षणिक फायदा, या छोटे से फायदे के लिए खेत में आग लगा देते हैं यह हमारे लिए कितना घातक (नुकसान) हो सकता है। आप क्या जानते हैं कि यदि हमने घास तथा पत्तियों को जलाया और उससे जो अवशेष बचता है जिसको (राख) या भस्म कहते है। आप सोचिए इसमें क्या हम लोग बीज को उगा सकते हैं या पोधों को उगा सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं उगा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बिना सोचे समझे खेत में आग लगा देते है इससे हमारे जमीन में विद्यमान लाखों करोड़ों लाभदायक सुक्ष्म जीव, जो कि खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं ओर मिट्टी बनाने में सहायता करते हैं वह सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। साथ ही किसान का मित्र केंचुआ भी नष्ट हो जाता, जो खाद बनाने का कार्य करता है जिसको खाद बनाने की मशीन भी कहते हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों को भूल करके अपने खेत में आग नहीं लगाना चाहिए। आग लगाने के बजाय कटाई के बाद जो

फसल का अवशेष बचता है उसमें कल्टीवेटर की सहायता से या हेरो की सहायता से या प्लाऊ की सहायता से उसी खेत में मिट्टी में मिला देना चाहिए। इससे खेत में ही बिना खाद डाले खाद बनाकर तैयार हो जायेगी। इस खाद से हमारी जमीन की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे फसलों की पैदावार मैं भी इजाफा होगा।

तीन दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित

मशरूम उत्पादन के लिए कृषि अवशेष और स्थान, श्रम पर्याप्त उपलब्ध

ग्वालियर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र ग्वालियर द्वारा युवाओं के लिये भारतीय कौशल विकास परिषद द्वारा प्रायोजित मशरूम उत्पादक का तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुये केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसएस कुशवाह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन के लिए कृषि अवशेष, स्थान, श्रम उपलब्ध तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृषक इसका उत्पादन छोटे स्तर पर कर रहे है इसकी वैज्ञानिक तकनीक द्वारा वर्ष भर अलग-अलग मशरूम का उत्पादन करके इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। केन्द्र के वैज्ञानिक का अरविन्दर कौर ने हीगरी तथा बटन मशरुम उत्पादन की सैद्धातिक तथा व्यावहारिक जानकारी प्रशिक्षण में दी। डॉ. सुरुचि सोनी गृह वैज्ञानिक ने मशरूम उत्पादकों को मशरूम के मूल्य संवर्धित उत्पादों की विस्तृत जानकारी दी। मशरुम बीज विक्रेता जी संजय कटोरे ने मशरूम बीज के उत्पादन तथा उनके यहां उपलब्ध विभिन मशरुम के बीज के बारे में प्रशिक्षार्थियों को बताया। प्रशिक्षण में पादप रोग विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष एव प्राध्यपक डॉ. रीति सिंह ने मशरूम उत्पादन में खाद्य एवं अखाद्य मशरुम की जानकारी दी। तथा मशरूम के बारे में विस्तृत चर्चा की।

मशरूम की विदेशों में मांग बढ़ रही

मशरूम की उगाने के लिए मशरूम घर की संरचना तथा वातावरण के बारे में मशहन उत्पादक मुकुल एवं आकाश ने प्रशिक्षार्थियों को जानकारी दी। मशरुम में लगने वाले कीटो के बारे में डॉ. एसपीएस तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एव रोगों के बारे में डॉ. जेसी गुप्ता वैज्ञानिक के वी के शिवपुरी ने पावर पाइंट प्रेंजेटेशन द्वारा दिया गया। केन्द्र के वैज्ञानिक अर्थशास्त्र विशेषज्ञ डॉ. एस सौ श्रीवास्तव एवं मशरूम विक्रेता एचएस गोस्वामी ने ब्रान्डिंग, उन्नत पैकिंग, प्रचार प्रसार द्वारा मशरूम के विभिक उत्पादों को प्रसंस्करण कर बाजार में बेचने के गुर सिखाए क्योंकि मशरूम की विदेशों में मांग बढ़ रही है। मशरूम को सुखाकर आधुनिक उपकरण जैसे द्वायर द्वारा सुखाकर बेचकर लाभ कमाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के तृतीय दिन प्रशिक्षार्थियों का मूल्याकंर किया गया इस कार्यक्रम में 50 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक श्री अन्न योजना

कुपोषण को दूर करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं मोटे अनाज

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

देश के जो भी किसान मोटे अनाज की खेती करते हैं, उनकी गरीबी दूर करने के साथ साथ आमदनी में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023-24 के आम बजट में 'श्री अन्न' योजना की घोषणा की थी। भारत सरकार ने श्री अन्न (मोटे अनाज) योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी साथ ही साथ आम नागरिकों के स्वास्थ्य को भी दुरुस्त रखने का काम करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को श्री अन्न का हब बनाने एवं इसके उत्पादन को बढ़ावा देने का है। इससे मोटे अनाज का निर्यात भी बढ़ेगा जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपको बता दें, मोटे अनाज वाली फसलों में ज्वार, बाजरा, रागी, सावां, कौनी, चीना कोदो, कुटकी और कुटू को श्री अन्न मिलेट्स कहा जाता है। इन मिलेट्स को सुपर फूड के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि इनमे पोषक तत्व की काफी अच्छी मात्रा होती है। भारतीय मिलेटस अनुसंधान संस्थान के अनुसार प्रति 100 ग्राम रागी में 364 मिलिग्राम तक कैल्शियम होता है। इसमें आयरन की मात्रा भी गेहूं और चावल से ज्यादा होता है। मिलेट्स क्रॉप को कम पानी की जरूरत होती है। बाजरा जैसे माटे अनाज की फसल के एक पौधे को पूरे जीवनकाल में 350 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है। जहां दूसरी फसलें पानी की कमी होने पर खराब हो जाती है, वही मोटे अनाज की फसल खराब होनी की स्थिति में भी पशुओं क चारे के काम आ सकती है।

पोषक तत्वों से भरपूर श्री अन्न

श्री अन्न कुपोषण दूर करने मे महतवपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत के लोगो में आइरन और जिंक सहित अन्य पोषक तत्वों की कमी होने से कुपोषण की समस्या हो जाती है, जिसे दूर करने में श्री अन्न बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत में आज लगभग 50 फीसदी जनसंख्या (इनमे 61 फीसदी गर्भवती महिलाएं है) में आयरन की कमी देखी जाती है। जीवन शैली, दिनचर्या और खान-पान के कारण भारत सहित पूरे विश्व में मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय और पाचन संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत के संदर्भ में बात करें तो ये रोग अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैर पसारने लगे हैं। कुछ दशक पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के रोगियों की संख्या नगण्य हुआ करती थी। इसका एक प्रमुख कारण मोटे अनाजों का भोजन में उपयोग करने के साथ नियमित दिनचर्या भी थी।

मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। जिससे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मोटे अनाजों को लेकर जन जागरूकता तेजी से फैल रही है। भारत सहित कुछ देशों में मोटे अनाजों का पहले से ही उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन कृषि में नए-नए अनुसंधान और खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि में आए परिवर्तन से मोटे अनाजों की लोकप्रियता में कमी आ गई थी। लेकिन जब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इसके प्रति जन जागरूकता बढ़ रही है और आने वाले समय में निश्चित ही वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों के खाद्य पदार्थ लोकप्रियता के शिखर को अवश्य छुएंगे।

योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान

भारत सरकार ने श्री अन्न योजना के कार्यान्वयन के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने का योजना प्रस्तावित है। भारत सरकार देश को श्री अन्न का हब बनाने की दिशा में व्यापक तैयारी कर रही है। इसमें भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मोटे अनाजों की उन्नत किस्मों के साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। इस केंद्र से देश के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सहित 14 राज्यों को तकनीकी सहायता मिल रही है। सरकार ने इंटरनेशनल मिलेट इंस्टीट्यूट स्थापित करने की भी घोषणा की है। इससे आदिवासी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष फायदा होने की संभावना है।

किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे बनवाएं, जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारत सरकार ने 19 फरवरी 2015 को एक ऐसी योजना की शुरुआत की थी, जो मिट्टी की सेहत से जुड़ी थी। इस योजना को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तौर पर जाना गया था। इस योजना का मकसद मिट्टी के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति को जानकर और उसका आकलन करना है। सरकार की तरफ से बताया गया था कि मिट्टी में अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड की मदद से किसान उस कमी को दूर कर सकते हैं। इस कार्ड को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से संचालित किया जा रहा है। साथ ही हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसका संचालन किया जा रहा है।

किसानों को क्या है फायदा- विशेषज्ञों की मानें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। उनका कहना है कि भारत में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम वो ज्यादा से ज्यादा फसल हासिल करने के लिए किस तरह की फसलें लगा सकते हैं। असल में, उन्हें अपनी मिट्टी की गुणवत्ता और प्रकार का पता नहीं होता। वे अनुभव से जान सकते हैं कि कौन सी फसलें उगती हैं और कौन सी फसलें खराब हो जाती हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि मिट्टी की स्थिति सुधारने के लिए वे क्या कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में किसानों को हेल्थ कार्ड के जरिए जमीन की मिट्टी की जानकारी उपलब्ध करानी होती है। इन जानकारियों को देने का मकसद किसानों की फसल और उपज को बेहतर करना है ताकि किसानों को मुनाफा हो सके।

किन दस्तावेजों की जरूरत

सरकार इस योजना के जरिये करीब 14 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है। किसानों को हर तीन साल में मिट्टी की जांच करानी होती है ताकि उसकी गुणवत्ता का पता चल सके। इस योजना के तहत किसानों को एक रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाता है जिसकी मदद से वो अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। अगर किसी किसान को मृदा हेल्थ कार्ड बनवाना है तो उसके लिए उसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की जरूरत होती है।

केवल पानी का उपयोग करके की जाती है खेती

हाइड्रोपोनिक खेतीः सरकार दे रही किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

बिना मिट्टी की खेती भी होती है। खेती की इस पद्धति को हाइड्रोपोनिक खेती कहा जाता है। जिसमें किसान केवल पानी का उपयोग करके फसल उगाता है। साथ ही इसकी खास बात यह है कि इस तरह की खेती पर सरकार आपको काफी अच्छी सब्सिडी भी देती है। हाइड्रोपोनिक खेती में सिर्फ पानी की मदद से खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ मात्रा में रेत और कंकड़ की जरूरत है। साथ ही सरकार इस खेती पर किसानों को सब्सिडी भी देती है। आपको बता दें कि यह खेती पाइप के जरिए की जाती है। इसके लिए पाइपों पर छेद करके उनमें पौधे लगाए जाते हैं। पौधों की जड़ें पानी के पाइपों में डूबी रहती हैं। साथ ही पौधे के लिए सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व भी इस पानी में घुल जाते हैं। 15 से 30 डिग्री का तापमान आपके लिए उपयुक्त है। तथा आर्द्रता 80 से 85 फीसदी सही रहती है। यहां खास बात यह है की सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए किसानों को 50 फीसदी तक की सब्सिडी भी दे रही है।

किसान उठाएं अनुदान का लाभ

हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती करने के लिए किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही कई राज्य सरकारें भी इस पर सब्सिडी दे रही हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने सभी राज्यों के लिए सब्सिडी के अलग-अलग नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक इसके लिए आवेदन करने पर सब्सिडी दी जाती है। इस खेती में आप मेहनत की लागत से भी ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिना मिट्टी की खेती पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आप स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य और केंद्र सरकार की कृषि वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।

अब क्लोन बनाकर सहेजे जाएंगे लुप्त हो रहे पौधे

असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी में बनाई जा रही टिशू कल्चर लैब

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

समय के साथ-साथ कई जानवर पौधे विलुप्त हो गए हैं और अभी भी लगातार कई पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं। जिन्हें बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही प्रयास अब राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। दरअसल, दिल्ली के स्थानीय पौधों को बचाने के लिए वन विभाग असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी में टिशू कल्चर लैब बनाने जा रहा है। पौधों की प्रजातियों और पर्यावरण की रक्षा करना इसका लक्ष्य है। रिपोर्ट्स के अनुसार वन विभाग के अधिकारी ने कहा है कि विलायती कीकर की अधिकता से कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाना मुश्किल हो गया है। वन विभाग के एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने बताया कि यह प्रजातियां विलायती कीकर की वजह से नहीं पनप रही हैं। विभाग ने ऐसी प्रजातियों की एक लिस्ट भी बनाई है। इसमें हिंगोट, खैर, बिस्टेंदु, सिरिस, पलाश, चमरोड, दूधी, धऊ, देसी बबूल और कुलु आदि शामिल हैं।

अगर बिडर नहीं आया तो...

वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस लैब के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि बिडर नहीं आता है तो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को इस लैब को बनाने को कहा जाएगा। लैब को बोटैनिस्ट और वन कर्मचारियों की जरूरत होगी। विभाग को देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन से बोटैनिस्ट और वैज्ञानिकों की मदद मिलेगी। लैब तैयार होने के बाद, कई पौधे बड़े पेड़ों के प्लांट टिशू से तैयार किए जाएंगे। वहीं, बायो डाइवर्सिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये प्रोसेस सिर्फ काफी कम रह गए पौधों के साथ होनी चाहिए। जबकि इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि टिशू से पौधे बनाना एक तरह का क्लोन बनाना है। वन विभाग के अनुसार, पौधों को लगाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्लोनिंग स्टेज पर कोई बीमारी या वायरस नहीं है। इस लैब में उन प्रजातियों को रीजनरेट किया जाएगा, जो आसानी से नहीं मिल रही हैं।

ग्रामीण कारीगरों और उनके हस्तनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा

एब्सोल्यूट ग्राम्या देशभर में लांच करेगा 1500 ग्राम्या ई-स्टोर

Gramya's E-Store

भोपाल। जागत गांव हमार

समृद्ध ग्राम, समृद्ध भारत के तत्वावधान में एब्सोल्यूट ग्राम्या प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक 28 राज्यों में 1500 ग्राम्या ई-स्टोर लॉन्च करने का लक्ष्य बनाया है। ग्राम्या ई-स्टोर, ग्रामीण कारीगरों और उनके हस्तनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अग्रणी मंच है, जो अपनी पहुंच और प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाया जा सकेगा और पूरे भारत में ग्रामीण समुदायों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

स्थायी आजीविका का निर्माण होगा- ग्रामीण कारीगरों और वैश्विक बाजारों के बीच अंतर को जोड़ने के अपने दृढ़ मिशन से प्रेरित, ग्राम्या ई-स्टोर विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में उभरा है। 1500 स्टोरों की शुरुआत के साथ, मंच का लक्ष्य ग्रामीण कारीगरों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और दुनिया भर के उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना है, जिससे स्थायी आजीविका का निर्माण होगा और भारत की समृद्ध पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा।

ग्रामीण कारीगरों को मिलेगा वैश्विक मंचः डॉ. पंकज शुक्ला

इस अवसर पर एब्सोल्यूट ग्राम्या प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी, डॉ.पंकज शुक्ला ने इस विस्तार पहल के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा-हम देश भर में 1500 स्टोर लॉन्च करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं। यह विस्तार ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के हमारे दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता है। इन स्टोरों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य ग्रामीण कारीगरों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के लिए नए अवसर पैदा करना है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यह पहल न केवल ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में योगदान देगी बल्कि हमारे देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

ग्राम्या ग्रामीण भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध

ग्राम्या ई-स्टोर की विस्तार योजना ग्रामीण भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ग्रामीण कारीगरों को दुकानों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करके, मंच का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुविधाजनक बनाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और जिम्मेदार उपभोग की समर्थन करना है। ग्राम्या ई-स्टोर ग्रामीण कारीगरों और उनके हस्तनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अग्रणी ऑनलाइन बाजार है। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और भारत की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर दृढ़ ध्यान देने के साथ, ग्राम्या ई-स्टोर अपने अभिनव मांग आधारित मंच के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों और वैश्विक उपभोक्ताओं के बीच अंतर को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसा कि ग्राम्या ई-स्टोर देश भर में अपना विस्तार जारी रख रहा है, यह अधिक समावेशी और गांव उन्मुख समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में इस यात्रा में हाथ मिलाने के लिए हितधारकों, भागीदारों और उपभोक्ताओं को निमंत्रण देता है।

मध्यप्रदेश में अब दागी गेहूं भी खरीदेगी समितियां

मप्र में अब दागी गेहूं भी खरीदेगी समितियां

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों के लिए राहत की खबर है। पहले समितियों द्वारा किसानों का दागी गेहूं खरीदने से इंकार किया जा रहा था। जिन समितियों ने दागी गेहूं खरीदा था उसे भारतीय खाद्य निगम ने वापस कर दिया था। इससे किसानों में आक्रोश था और किसान संगठनों ने राज्य सरकार से चमकविहीन मामूली दागी गेहूं को भी खरीदने की मांग की थी। इसी कड़ी में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्जनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली के संयुक्त आयुक्त (एस एंड आर) द्वारा सोमवार को जारी आदेश में केंद्रीय पूल खरीद के लिए गेहूं की विशिष्टताओं में छूट दी गई है।

जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी विपणन सीजन 2024 -25 के लिए सरकार द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं की समान विशिष्टताओं में चमक हानि में छूट के साथ किसानों से गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के उल्लेख किया गया है कि पूरे मध्यप्रदेश में 30 फीसदी तक प्रभावित दानों वाला चमक विहीन गेहूं किसानों से बिना किसी मूल्य कटौती के खरीदा जाएगा। खरीदे गए गेहूं को ढेर में रखा जाएगा और उसका हिसाब अलग से लगाया जाएगा। भंडारण के दौरान शिथिल मापदंडों के तहत खरीदे गए गेहूं स्टॉक की गुणवत्ता में

किसी भी तरह की गिरावट की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की रहेगी। इसके अलावा खरीदे गए गेहूं के स्टॉक को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। इस छूट के कारण किसी भी वित्तीय या परिचालन प्रभाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी। इस निर्णय से अब किसानों को राहत मिल गई है। अब वे अपना चमकहीन गेहूं समितियों में बेच सकेंगे।

अब किसानों की परेशानी होगी दूर

उल्लेखनीय है कि रबी सीजन 2024 -25 में समिति स्तर और गोदाम स्तर पर भारतीय खाद्य निगम के निर्देश अनुसार गेहूं खरीदी में मापदंड और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान उपार्जित स्टॉक के नमूनों का विश्लेषण करने पर इसे मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस स्टॉक के वापस/ रिजेक्ट करने पर उसकी समस्त जवाबदेही समिति की बताए जाने पर समिति प्रबंधकों ने उपार्जन केंद्रों पर माल की तुलाई बंद कर दी थी, जिससे किसान परेशान हो रहे थे।

सब्सिडी पर मिलेंगे सिंचाई उपकरण 15 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित

भोपाल। जागत गांव हमार

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा वर्ष 2024- 2025 के लिए निम्नलिखित योजनाओं अंतर्गत सिंचाई उपकरणों के लिए 8 अप्रैल 2024 से 15 मई तक कृषकों से पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं । किसानों से प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध ऑनलाइन लॉटरी सम्पादित की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जाएगी। जिन सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उनके लक्ष्यों का विवरण इस प्रकार है...।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन)- स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम
- राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन - स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट(डीजल/ विद्युत), पाइप लाइन सेट।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन - स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्यु) ।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं - स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट, पंपसेट(डीजल/ विद्युत), रेनगन सिस्टम ।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा - स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन ।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान- पाइप लाइन सेट, पंपसेट(डीजल/ विद्युत) तथा
- बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन- स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट, पंपसेट(डीजल/ विद्युत) शामिल हैं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)